

# यूपी के हस्तशिल्प, कृषि, रेडीमेड और लेदर इंडस्ट्री की लगी लॉटरी

लखनऊ। भारत और यूरोपीय संघ के बीच हुए ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते का सीधा और सकारात्मक असर उत्तर प्रदेश पर पड़ेगा। इससे प्रदेश की औद्योगिक क्षमता, कृषि उत्पादन और एमएसएमई सेक्टर को नई रफ्तार मिलेगी। भारत के प्रमुख आयात-निर्यात वाले देशों में अमेरिका के अलावा जर्मनी, यूके, फ्रांस, स्पेन, नीदरलैंड, इटली, स्विटजरलैंड आदि देश हैं।

यूपी से होने वाले कुल निर्यात में यूरोपीय संघ की हिस्सेदारी 9 से 12% है। यानी हर वर्ष यूपी से करीब 20 हजार करोड़ का निर्यात होता है। अगले पांच वर्ष में ये बढ़कर



40 हजार करोड़ होने की उम्मीद है। इस ट्रेड डील से कपड़ा, परिधान, चमड़ा, रत्न व आभूषण, हस्तशिल्प, चाय, मसाले और समुद्री उत्पाद जैसे श्रम-प्रधान क्षेत्रों के साथ ही इंजीनियरिंग सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा व मेडिकल उपकरणों से जुड़ी इंडस्ट्री की लॉटरी लगने की संभावना है।

कानपुर व आगरा के चमड़े के जूते निर्यातक अपना निर्यात बढ़ा सकते हैं। चर्म निर्यात परिषद के चेयरमैन आरके जालान और नेशनल स्किन डेवलपमेंट काउंसिल के सदस्य व चर्म निर्यात परिषद के पूर्व अध्यक्ष मुख्तारुल अमीन ने कहा, अमेरिकी टैरिफ की चुनौतियों का सामना करने में ये डील निर्णायक साबित होगी। अगले पांच वर्ष में यूरोपीय संघ से कारोबार दोगुना होगा।

सहारनपुर फर्नीचर और हस्तशिल्प निर्यात से लाभान्वित होगा। नोएडा के इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग और पश्चिम यूपी के कृषि उत्पादों को भी लाभ होगा,

जिससे यूपी के निर्यात का दायरा बढ़ेगा। रेडीमेड गारमेंट्स, कालीन, कांच उद्योग व बनारसी साड़ी जैसे पारंपरिक उत्पादों के निर्यात में 50% से ज्यादा तेजी आएगी।

अर्थ विशेषज्ञ डॉ. एमके सिंह के मुताबिक यूपी देश का बड़ा कृषि उत्पादक राज्य है। समझौते से बासमती चावल, आम, आलू उत्पाद, डेयरी और प्रोसेस्ड फूड के निर्यात को बढ़ावा मिल सकता है। यूरोपीय बाजार में गुणवत्ता आधारित मांग अधिक है, जिससे फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स और कोल्ड चैन इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूती मिलेगी। ब्यूरो